

मुख्य समाचार''

- राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामूहिक भागीदारी पर दिया बल।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा—उर्जा उपलब्धता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी पम्प स्टोरेज परियोजनाएं।
- विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के अनुसार—सतत व समावेशी विकास देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर औद्योगिक क्षेत्रों को परेशान करने का लगाया आरोप।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि सामूहिक भागीदारी से ही स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। राज्यपाल आज शिमला जिला के फागू में 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिला पंचायत प्रतिनिधियों और स्वयं सहायता समूहों की 'दीदियों' से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन सफलतापूर्वक 10वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान मनाया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि इस अभियान के तहत स्वच्छता लक्ष्य, स्वच्छता में जन भागीदारी और सफाई मित्र सुरक्षा शिविर केन्द्र में रहेंगे। शिव प्रताप शुक्ल ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जन अभियान में लोगों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने में पंचायत प्रतिनिधि और महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित स्वास्थ्य शिविर का शुभारम्भ भी किया। इसके अलावा राज्यपाल ने देवदार का पौधा रोपित कर वन विभाग के पौधरोपण अभियान का शुभारम्भ भी किया।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पंप स्टोरेज परियोजनाएं सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बिजली आपूर्ति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि हाल ही

में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सिरमोर जिला की एक हजार 6 सौ 30 मेगावाट की रेणुका जी पंप स्टोरेज परियोजना और मंडी जिला के ब्यास बेसिन में 2 सौ 70 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए आदर्श राज्य है और प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए वरदान हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रेणुका जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्षमता 40 मेगावाट होगी, जबकि थाना प्लौन जल विद्युत परियोजना एक सौ 91 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हाइड्रो परियोजनाओं के माध्यम से राजस्व बढ़ाने और हिमाचल को एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विक्रमादित्य सिंह

लोकनिर्माण निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में स्ट्रीट वैंडर पॉलिसी को सख्ती से लागू किया जाएगा। मस्जिद विवाद को लेकर उन्होंने आज शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शिमला में एक हजार 60 स्ट्रीट वैंडर पंजीकृत हैं जबकि 5 सौ 40 लोग ऐसे ही बैठे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इसमें कमेटी देखेगी की नियमों के तहत कहां किसको जगह देनी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वैंडर सर्वे में त्रुटियां हैं और उस पर संज्ञान लिया गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्ट्रीट वैंडर के लिए ब्लू लाईन तय की जाएगी और स्ट्रीट वैंडर को फोटो के साथ अपनी पहचान दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि ये सारी प्रक्रिया 30 दिसम्बर तक पूरी कर ली जाएगी।

महिला सशक्तिकरण

केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, किसानों, मध्यम वर्ग की महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजना, शुरू की है। सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के विकास के लिए एक मजबूत पहल की है।

मन की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश-विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। लोग कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 के जरिए दे सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ट कॉल भी दे सकते हैं और नरेंद्र मोदी ऐप या माईगोव ओपन फोरम के जरिए भी अपने सुझाव ऑनलाइन साझा कर सकते हैं। लोग इस महीने की 27 तारीख तक अपने सुझाव भेज सकते हैं।

विधानसभा अध्यक्ष

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि सतत व समावेशी विकास वर्तमान समय में देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली स्थित संसद भवन में आयोजित दो दिवसीय भारत क्षेत्र राष्ट्रमण्डल संघ सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए आज उन्होंने ये बात कही। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सतत विकास का उद्देश्य दीर्घकालिक व संतुलित विकास को सुनिश्चित करना है जबकि समावेशी विकास विशेष रूप से समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर प्रदान करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने पर केन्द्रित करना है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सतत व समावेशी विकास में विधायिका की अहम भूमिका है ऐसे में हमें अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखना होगा। दो दिवसीय इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला और राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश सहित राज्य विधान मण्डलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पीठासीन अधिकारियों ने भी भाग लिया।

जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि सत्ता में आने के बाद से कि प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को परेशान करने का काम कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार माफिया के प्रभाव में उद्योगों पर सरकारी नीतियों का दबाव डाल रही है और उद्योगपतियों का डराया—धमकाया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज सरकार ने उद्योगों को इस स्थिति में ला दिया है कि वे शटडाउन कर अपना विरोध दर्ज करवाने की योजना बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी में सहयोग और रोजगार देने वाले उद्योगों को परेशान करके सरकार राज्य की आर्थिकी को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में विभिन्न स्तरों पर उद्योगों को रियायत दी जाती है ताकि औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिल सके लेकिन प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते उद्यमी हिमाचल से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं।

भाजपा

प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पानी व बिजली के रेट बढ़ाए जाने की कड़ी निंदा की है। शिमला से जारी एक संयुक्त बयान में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्बाल, कांगड़ा से पार्टी प्रवक्ता संजय शर्मा और संदीपनी भारद्वाज व विनोद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही जनता पर महंगाई का बोझ डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है और मनरेगा की दिहाड़ी करने वाले लोगों पर पानी के बिल लगाकर सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण जनता में रोष है और सरकार बनने के पहले साल से ही लोग सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे हैं।

कर्मचारी महासंघ

प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने राज्य सरकार से कर्मचारियों के डी.ए. की किश्त और लम्बित एरियर का भुगतान जल्द करने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र चौहान ने चम्बा में

आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कर्मचारियों की चार डी.ए. की किश्तें लम्बित हो गई हैं। ऐसे में सरकार को दीपावली तक कम से दो किश्तें जारी करनी चाहिए। उन्होंने अनुबंध कर्मचारियों को साल में दो बार नियमित करने की पुरानी व्यवस्था को दोबारा शुरू करने और प्रदेश के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को नियमित करने की भी मांग की।

डीसी शिमला

प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों और समाज के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने सहित सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए अपना विद्यालय-द हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी कड़ी में शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आज उनके द्वारा गोद लिए गए राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मशोबरा का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि स्कूली शिक्षा का आधार अगर मजबूत होगा तो हर लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। उपायुक्त ने स्कूल परिसर के साथ भू-स्खलन के कारण बाधित हुए मार्ग और भवन के लिए खतरा बने क्षेत्र में जल्द डंगा लगाने के अधिकारियों को निर्देश दिए।

मुख्य समाचार एक बार फिर”

- राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामूहिक भागीदारी पर दिया बल।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा—उर्जा उपलब्धता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी पम्प स्टोरेज परियोजनाएं।
- विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के अनुसार—सतत व समावेशी विकास देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर औद्योगिक क्षेत्रों को परेशान करने का लगाया आरोप।